UPSC संपादकीय लेख विश्लेषण 28 जुलाई 2021

संपादकीय लेख 1: एक तस्करी-विरोधी कानून की आवश्यकता

टॉपिक: सामान्य अध्ययन 2 (सामाजिक न्याय)

संदर्भ:

- सीता केवल 13 वर्ष की थीं, जब उसकी तस्करी की गई थी और उनके माता-पिता असम में एक चाय बागान में अत्यंत कम मजदूरी पर काम करते थे, ऐ जोड़े द्वारा सीता की एक घरेलू नौकर के रूप में 20,000 रूपये में एक प्लेसमेंट एजेंसी में तस्करी की गई थी, जहां उसे एक रूपए का भी भुगतान नहीं किया गया था, इसके बजाय, नियोक्ताओं और तस्करों द्वारा उसकी फिर से तस्करी, बलात्कार और शोषण किया गया था।
- तीन वर्ष बाद, जब सीता के पिता ने लड़की को एक घर में पाया तो वह बाहर नहीं निकली बल्कि यह कहकर छिप गई कि "मैं अपने पिता को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूं। मैं अब अशुद्ध हूँ। मैं खुद को मार डालना चाहती हूँ।
- सीता की तरह, हमारे समाज के सबसे गरीब वर्ग की हजारों महिलाएं और बच्चे ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं।
- एक राष्ट्र भले ही धन, शक्ति या राष्ट्र की प्रगति में विकास करता है, लेकिन मध्ययुगीन दास व्यापार के समान अपनी बेटियों की खरीद-बिक्री को सहन करता है तो उसे सभ्य नहीं कहा जा सकता है।

एक व्यापक विधेयक

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- बचपन बचाओ आंदोलन (BBA) जैसे विभिन्न सिविल सोसाइटी समूह और अन्य, मानव तस्करी के इस खतरे को समाप्त करने के लिए एक मजबूत कानून के लिए दशकों से अभियान चला रहे हैं।
- वर्ष 2017 में, सीता और उसके जैसे हजारों बचे लोगों ने छात्रों, सरकारों, न्यायपालिका, बहुधर्मी नेताओं, व्यवसायों और सिविल सोसाइटी के साथ-साथ तस्करी विरोधी कानून की मांग करते हुए भारत यात्रा में मार्च किया था।
- लगभग 12 लाख लोगों ने "बिकने को तैयार नहीं हम,, लुटने को तैयार नहीं हम" जैसे नारों का उपयोग करके 12,000 किलोमीटर पैदल चलकर यह मांग की थी कि भारत को व्यापक तस्करी विरोधी कानून पारित करना चाहिए।
- हाल ही में, सरकार ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 प्रस्तावित किया है।
- इस विधेयक का उद्देश्य तस्करी के सभी पहलुओं से निपटना है, जिसमें अपराध के सामाजिक और आर्थिक कारण, तस्करों को सजा देना और बचे हुए लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास कराना शामिल है।
- एजेंसियों द्वारा शक्ति के संभावित दुरूपयोग के खिलाफ आवश्यक जांच और संतुलन, कानून की समय-समय पर समीक्षा और संसाधनों के पर्याप्त आवंटन से विधेयक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है।

कोविड द्वारा बदतर हुई समस्या

- वैश्विक महामारी के दौरान, तस्करी की स्थिति और भी खराब हो गई है क्योंकि तस्कर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने और पारिवारिक आजीविका के नुकसान का फायदा उठा रहे हैं।
- सरकारी एजेंसियों और बीबीए ने मिलकर पहले लॉकडाउन के बाद से लगभग 9,000 बच्चों को तस्करी से बचाया है, जबकि उनमें से केवल 50% को ही वैश्विक महामारी से पहले की समान अवधि के दौरान बचाया गया था।
- तस्करी की वर्तमान स्थिति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, इसके बजाय इसके मानव प्रभाव को संबोधित करने के लिए तस्करी कानून और इससे संबंधित बजटों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
- मानव तस्करी अपने आप में एक अपराध है और बाल श्रम, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, जबरन भीख मंगावाना, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अन्य अवैध व्यापारों जैसे अन्य अपराधों के लिए समानांतर काली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर कई अन्य अपराधों का प्रेरक भी है।
- यहां तक कि भारत के संविधान ने भी अस्पृश्यता के अतिरिक्त तस्करी को भी भारत के संविधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध बना दिया है।

निष्कर्ष:

- ✓ एक मजबूत तस्करी-रोधी कानून बनाना और उसे लागू करना हमारे निर्वाचित नेताओं की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है और राष्ट्र निर्माण और आर्थिक प्रगति की दिशा में एक आवश्यक कदम है।
- ✓ भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, अपने बच्चों की स्वतंत्रता से बढ़कर भारत के लिए कोई उपहार नहीं हो सकता है, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था, हमारे सैनिक मारे गए थे और हमारे बच्चे इसके हकदार हैं।
- ✓ यह सही समय है कि सरकार एक मजबूत मानव तस्करी-रोधी कानून पारित करे।

स्रोत:

Needed: an anti-trafficking law: https://thg.page.link/BRdgLv2GZT3pKkUp8

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

संपादकीय लेख 2:
अफगानिस्तान के लिए एक अधिक एकीकृत एशियाई आवाज की आवश्यकता

टॉपिक: सामान्य अध्ययन (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ:

- चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति समाप्त करने का फैसला किया है, मध्य एशिया एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, जिसकी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के वैश्विक ट्रॉइका (नेता) रूख कर रहे हैं।
- एक महीने के भीतर, अफगानिस्तान पर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) संपर्क समूह और ताजिकिस्तान में SCO रक्षा मंत्रियों और उज्बेकिस्तान में क्षेत्रीय संपर्क पर मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन के बीच 3 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, जो अफगानिस्तान में स्थिति से निपटने में क्षेत्र की भूमिका को उजागर करता है और भारत उस पर कैसे निर्माण कर सकता है।

तालिबान में आढ़तिया दलाली

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- पिछले वर्षों में, ट्रॉइका ने भारत को अफगानिस्तान में अग्रणी भूमिका से बाहर रखा है।
- हालांकि, 2019 से, जब ट्रॉइका ने अफगानिस्तान की भविष्य की चर्चा में पाकिस्तान (ट्रॉइका प्लस) को शामिल किया था तो भारत को भी भाग लेना चाहिए, हालांकि तालिबान के साथ इसकी कोई भूमिका नहीं है।
- अमेरिका जिसने 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया था और तालिबान नेतृत्व को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित आतंकवादी के रूप में घोषित किया गया था, अब तालिबान के साथ बातचीत की वकालत नहीं कर रहा है, मदद के लिए अपने पाकिस्तानी मेजबानों से आग्रह कर रहा है और सक्रिय रूप से तालिबान की सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

अफगानिस्तान में भारत के विकल्पों का मूल्यांकन करना:

भारत के पास अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने, विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और अफगान युवाओं के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाने का दृष्टिकोण है, लेकिन यह कई कारकों के कारण बड़ा नहीं हो सकता है।

1. भारत तालिबान के साथ खुली बातचीत करने में झिझक रहा है, जिसका सुझाव अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी दिया था, जिसने भारत को मौजूदा सुलह प्रक्रिया से बाहर कर दिया है।

2. भारत-पाकिस्तान के खराब संबंधों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारत की जमीनी पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है और अब भारत केवल चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है, जो व्यवहार्य या लागत प्रभावी नहीं है और जब तक ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं।

3. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव और 2017 में भारत द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के बहिष्कार के कारण अफगानिस्तान के लिए एक और मार्ग अवरूद्ध हो गया है।

4. अमेरिका ने क्षेत्रीय संपर्क अमेरिका-उजबेकिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान पर एक "क्वाड" के एक नए गठन की घोषणा की है, जिसमें भारत शामिल नहीं है।

5. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) ताशकंद से कराची और कराची से ताशकंद के लिए ट्रक परिवहन हेतु एक परीक्षण कर रही है।

इतनी सारी बाधाओं के बाद, एक संभावना थी कि मध्य एशियाई खिड़की, "स्टैन्स" (कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के पांच मध्य एशियाई गणराज्य) के साथ नई संभावनाएं हैं, लेकिन वहां भी कुछ विरोध है।

उजबेकिस्तान का दृष्टिकोण

- 2016 में सत्ता में आने के बाद ताशकंद (उजबेकिस्तान) ने अपने संबंधों में सुधार किया है और अन्य मध्य एशियाई राज्यों में से प्रत्येक के साथ सीमा विवादों को समाप्त किया है और मॉस्को की ओर पारंपरिक झुकाव को स्थानांतरित करने के लिए अमेरिका और चीन तक पहुंच बनाई है।
- उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने 2018 में अफगानिस्तान पर उद्देश्यपूर्ण कदम उठाए हैं, उनकी सरकार दोहा से तालिबान प्रतिनिधिमंडल को सार्वजनिक रूप से आमंत्रित करने वाले पहले देशों में से एक बन गई है।
- ताशकंद, अशरफ गनी सरकार के साथ कई महत्वाकांक्षी व्यापार और संपर्क पहलों को भी बढ़ावा दे रहा है।

कनेक्टिविटी के लिए एक बढ़ावा

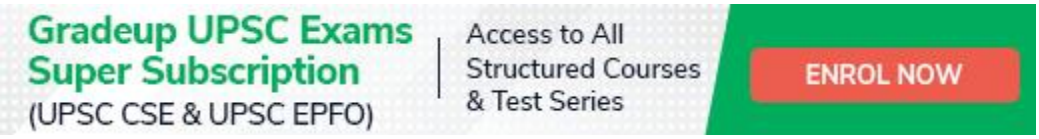

- उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव "उत्तर पथ के रूप में जाने जाने वाले प्राचीन उत्तरी व्यापार मार्ग के आधुनिक संस्करण की योजना बना रहे हैं, जो तक्षशिला, गांधार और तर्मेज़ के ऐतिहासिक शहरों के माध्यम से यूरेशियाई महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ भारत-गंगा के मैदान को भी जोड़ता है।
- उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति का मत पुराने रेशम मार्गों को पुनर्जीवित करने का भी है, जो मध्य और दक्षिण एशिया को एक साथ जोड़ेंगें और अफगानिस्तान उनके लिए "व्यावहारिक संपर्क" में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
- मिर्जियोयेव ने "कनेक्टिविटी की वास्तुकला" के प्रमुख तत्वों के रूप में तरमेज़-मज़ार-ए-शरीफ़-काबुल-पेशावर रेलमार्ग, चीन के BRI को जोड़ने के लिए ट्रांस-अफगान रेलमार्ग और बंदर अब्बास के ईरानी बंदरगाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के महत्व पर भी जोर दिया है, लेकिन उन्होंने चाबहार मार्ग की अनदेखी की है, जिसे भारत ने सुझाया था।
- इसके साथ ही, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के बीच पारगमन व्यापार पर समझौते (AUPTT) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो उज्बेकिस्तान को ईरानी बंदरगाहों के बजाय ग्वादर और कराची के पाकिस्तानी बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करेगा।

उजबेकिस्तान के अनुमान:

1. उज्बेकिस्तान सोचता है कि इन स्थल-सीमा मध्य एशियाई देशों की समृद्धि केवल अफगानिस्तान के माध्यम से निकटतम महासागर अर्थात हिंद महासागर तक पहुंच से प्रवाहित हो सकती है।

2. अफगानिस्तान के माध्यम से सभी सफल पारगमन के लिए पाकिस्तान में समूह के आकाओं द्वारा समर्थित तालिबान द्वारा सुरक्षित मार्ग की गारंटी की आवश्यकता है।

3. व्यापार, निवेश और पाकिस्तान पर कुछ हद तक नियंत्रण बढ़ाने के लिए प्रत्येक "स्टैन" अब चीन के BRI का हिस्सा है।

साझाकृत चिंताएं:

- हालांकि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच बातचीत की उम्मीद कम है, भारत मध्य एशिया के साथ समान चिंताओं पर बातचीत शुरू कर सकता है, जैसे कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा और पाकिस्तान के नियंत्रण में उनकी सीमाओं पर लड़ाई की चिंता, अफगानिस्तान में जिहादी आतंकी समूहों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल और अपने स्वयं के देशों में उत्कटवाद का प्रसार हैं।
- भारत और उसके पड़ोसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि अफगानिस्तान के वित्त पोषण को सुनिश्चित करने में सरकारी ढांचा ढह न जाए।
- SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे (RATS) के हिस्से के रूप में, भारत को आतंकवाद से लड़ने में मध्य एशियाई देशों के साथ भी जुड़ना चाहिए।
- भारत हवाई शक्ति के संदर्भ में अफगान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बलों (ANDSF) का समर्थन कर सकता है।
- भारत के साथ अफगानिस्तान की पहली रणनीतिक साझेदारी 10 वर्ष पहले थी और फिर भारत ने कुछ हेलीकॉप्टर उपहार में दिए थे, जो पर्याप्त नहीं हैं, नई दिल्ली अन्य देशों के साथ सहयोग कर सकती है, जो सोवियत निर्मित हथियारों पर निर्भर हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर और विमान, हथियार, गोला-बारूद और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। .

पाकिस्तान से निपटना

- केवल भारत और पाकिस्तान के बेहतर संबंध ही इस क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- भारत को दोहा में तालिबान नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श के साथ ही क्षेत्र में शांति के लिए पाकिस्तान के साथ और अधिक सामरिक संबंध बनाने चाहिए।
- मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के देशों के पास अधिक एकीकृत आवाज होनी चाहिए और उन्हें यह समझना होगा कि अफगानिस्तान का भविष्य दोनों क्षेत्रों को उससे कहीं अधिक प्रभावित करेगा, जितना कि वर्तमान में बहस में प्रभुत्व रखने वाली वैश्विक शक्तियों को कर रहा है।

निष्कर्ष:

- ✓ वर्ष 2015 में, कजाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मध्य और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाली सिल्क रोड न केवल नई यूरोपीय शक्तियों के समुद्र-आधारित व्यापार के उदय के कारण फीकी पड़ गई है बल्कि इसलिए भी कि मध्य एशिया अब क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में काम नहीं कर पा रहा था बल्कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में महान साम्राज्यों के बीच नई फाल्ट लाइन बन गई है।
- ✓ समान प्रकार से, वर्तमान में अफगानिस्तान में वह पुल बनने या मध्य और दक्षिण एशिया के बीच सबसे बड़ा शिलाखंड बनने की क्षमता है और भारत को तालिबान के साथ खुली बातचीत शुरू करनी चाहिए और क्षेत्र की स्थिरता के लिए अफगानिस्तान के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए।

स्रोत:

Needed, a more unified Asian voice for Afghanistan: https://thg.page.link/YsWvdi4cJEHEcsgz7

gradeup

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW